नईदुनिया

भोपाल, 29 अगस्त 2026

5,000 करोड़ की पीआरआईपी योजना से फार्मा-मेडटेक नवाचार को मिलेगा बढ़ावा

स्टार्टअप, एमएसएमई और उद्योगों के लिए आवेदन का दूसरा अवसर, सितंबर मध्य से शुरू होगी प्रक्रिया

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के औषधि विभाग ने फार्मा एवं मेडटेक में अनुसंधान एवं नवाचार प्रोत्साहन (पीआरआईपी) योजना के तहत आवेदन आमंत्रित करने की दूसरी तिथि की घोषणा की है। 5,000 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय वाली इस योजना का उद्देश्य देश में फार्मास्युटिकल और मेडटेक अनुसंधान एवं विकास पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है। योजना के माध्यम से स्टार्टअप, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा बड़ी कंपनियों को नवाचार मूल्य श्रृंखला में आगे बढ़ने में सहायता दी जाएगी।

योजना के तहत दो श्रेणियों में आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। प्रारंभिक चरण में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी तत्परता स्तर (टीआरएल) 1, 2 या 3 पर मौजूद उत्पादों और प्रौद्योगिकियों को टीआरएल 5 तक ले जाने वाली स्टार्टअप और एमएसएमई परियोजनाएं पात्र होंगी। इसके लिए दो चरणों वाली प्रक्रिया अपनाई जाएगी। पहले संक्षिप्त अवधारणा नोट प्रस्तुत करना होगा और चयनित आवेदकों को इसके बाद विस्तृत आवेदन देना होगा। इस श्रेणी में प्रति परियोजना पांच करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध होगी।

बाद के चरण की परियोजनाओं में उद्योग, स्टार्टअप और एमएसएमई की वे परियोजनाएं पात्र होंगी, जो प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में टीआरएल 4, 5 या 6 पर मौजूद उत्पादों अथवा प्रौद्योगिकियों को उच्चतर स्तर तक ले जाना चाहती हैं।

प्रति परियोजना अधिकतम 100 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता

इनके लिए विस्तृत आवेदन के माध्यम से सीधे आवेदन किया जा सकेगा। प्रति परियोजना अधिकतम 100 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह सहायता स्वीकृत कुल परियोजना लागत के अधिकतम 35 प्रतिशत तक सीमित होगी और शेष राशि आवेदक को सह-वित्तपोषित करनी होगी। पीआरआईपी पोर्टल पर आवेदन जमा करने की प्रक्रिया सितंबर के मध्य तक शुरू होगी। आवेदन पत्र और संबंधित दिशानिर्देश पीआरआईपी पोर्टल पर उपलब्ध हैं। आवेदक योजना दस्तावेज, अवधारणा नोट मार्गदर्शन, विस्तृत आवेदन दिशानिर्देश, माइलस्टोन डिस्क्रिप्टर कैटलॉग, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न और एप्लीकेशन सपोर्ट टूलकिट का भी उपयोग कर सकते हैं। योजना के पहले चरण में परियोजना जमा कर चुके आवेदकों से उसी परियोजना को दोबारा जमा नहीं करने का अनुरोध किया गया है।

पीआरआईपी योजना वर्ष 2023 में फार्मास्युटिकल क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसे क्षेत्र भी शामिल हैं। योजना के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में नई औषधियां, जटिल जेनेरिक और बायोसिमिलर तथा नवीन चिकित्सा उपकरण शामिल हैं। नवीन चिकित्सा उपकरणों में एआई/एमएल आधारित चिकित्सा उपकरण, आनुवंशिक प्रौद्योगिकी वाले निदान एवं स्क्रीनिंग उपकरण, रोबोटिक चिकित्सा उपकरण, टेलीमेडिसिन सुविधाओं वाले उपकरण और बायोमार्कर आधारित नए इन-विट्रो डायग्नोस्टिक उपकरण शामिल हैं।

खास-खबरें

टाटा कारों के लिए नया ब्रांड डीलरशिप और सर्विस व्यवस्था में बदलाव

नईदुनिया ब्यूरो, मुंबई: टाटा मोटर्स ने अपने पैसेंजर व्हीकल कारोबार की पहचान में बड़ा बदलाव किया है। कंपनी अब पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में अपनी कारों को नए नाम टाटा कार्स के तहत पेश करेगी। इस बदलाव के साथ कंपनी की ब्रांडिंग, डीलरशिप नेटवर्क और सर्विस व्यवस्था में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। टाटा मोटर्स लंबे समय से भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में अपनी कारों के लिए जानी जाती है। कंपनी ने अब अपने पैसेंजर व्हीकल कारोबार को अलग पहचान देने के उद्देश्य से यह कदम उठाया है। नए नाम के तहत कंपनी अपने मौजूदा और आने वाले मॉडल को बाजार में पेश करेगी।

कंपनी के अनुसार, यह बदलाव केवल नाम तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ग्राहकों के अनुभव को बेहतर बनाने पर भी ध्यान दिया जाएगा। डीलरशिप और सर्विस सेंटर की पहचान में भी बदलाव किया जाएगा, जिससे ग्राहकों को नई ब्रांडिंग के अनुरूप सुविधाएं मिल सकें। टाटा कार्स के नाम से कंपनी अपने पैसेंजर व्हीकल कारोबार को और मजबूत बनाने की योजना पर काम कर रही है। भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक वाहनों, एसयूवी और अन्य कार सेगमेंट में कंपनी की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। नए ब्रांड नाम के जरिए कंपनी ग्राहकों के साथ अपने जुड़ाव को और मजबूत करना चाहती है। टाटा मोटर्स के पोर्टफोलियो में नेक्सन, पंच, हैरियर, सफारी और अन्य लोकप्रिय मॉडल शामिल हैं। कंपनी लगातार नए तकनीकी फीचर्स और आधुनिक डिजाइन के साथ वाहनों को बाजार में उतार रही है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में कंपनियां अपने कारोबार को अलग-अलग पहचान देने के लिए ब्रांडिंग में बदलाव करती रही हैं। टाटा का यह कदम भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिससे पैसेंजर व्हीकल कारोबार को स्वतंत्र पहचान मिल सके।

रक्षा निर्यात नियमों में सुधार से वैश्विक बाजार तक आसान पहुंच

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग ने रक्षा निर्यात मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) और ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस (ओजीईएल) ढांचे को सरल बनाने के लिए व्यापक सुधार किए हैं। इन सुधारों का उद्देश्य भारतीय रक्षा कंपनियों के लिए प्रक्रियात्मक बाधाओं को कम करना, वैश्विक बाजारों तक पहुंच आसान बनाना और भारत को विश्वसनीय रक्षा विनिर्माण एवं निर्यात भागीदार के रूप में स्थापित करना है। रक्षा निर्यात एसओपी में बदलाव के तहत अधिकांश गंतव्यों के लिए गैर-घातक रक्षा वस्तुओं के निर्यात में हितधारकों से परामर्श की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है। हालांकि, संवेदनशील देशों के लिए सुरक्षा उपायों को बरकरार रखा गया है। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय निविदाओं और प्रदर्शनियों के लिए सभी वस्तुओं के निर्यात में भी परामर्श प्रक्रिया को समाप्त किया गया है, जिससे भारतीय कंपनियां अपने उत्पादों को तेजी से वैश्विक मंच पर प्रदर्शित कर सकेंगी। ओजीईएल एक स्थायी एकमुश्त निर्यात लाइसेंस है, जिसके माध्यम से पात्र निर्यातक निर्दिष्ट रक्षा वस्तुओं की आपूर्ति के लिए बार-बार मंजूरी लेने की आवश्यकता से बचते हैं। नए सुधारों के तहत प्रमुख प्लेटफॉर्म, उपकरण, पुर्जे, घटक और अंतर-कंपनी प्रौद्योगिकी हस्तांतरण से जुड़े तीन अलग-अलग ओजीईएल एसओपी को एकीकृत कर दिया गया है।

ओजीईएल की वैधता अवधि को दो वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष कर दिया गया है। इसके साथ ही इसका दायरा 41 देशों से बढ़ाकर सभी देशों तक कर दिया गया है, हालांकि नकारात्मक, संवेदनशील देशों और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रतिबंधों वाले देशों को इससे बाहर रखा गया है।नए प्रावधान के तहत विदेशी मूल उपकरण निर्माताओं के साथ दीर्घकालिक अनुबंध करने वाली भारतीय कंपनियों को भी सुविधा मिलेगी। इसके अलावा ओजीईएल के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं की श्रेणी का विस्तार किया गया है, जिससे छोटे हथियारों और सुरक्षा उपकरणों के कुछ पुर्जों एवं घटकों के नागरिक उपयोग के लिए निर्यात के अवसर बढ़ेंगे।

इन सुधारों से भारतीय रक्षा निर्माताओं, विशेषकर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को लाभ मिलने की उम्मीद है। इससे वे अंतरराष्ट्रीय निविदाओं और प्रदर्शनियों में तेजी से भाग ले सकेंगे तथा वैश्विक बाजारों तक बेहतर पहुंच बना सकेंगे।

एक सितंबर से देश में होंगे पांच बड़े बदलाव, घर-घर और जेब पर पड़ेगा असर

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: सितंबर की शुरुआत के साथ देश में कई महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों के घर के बजट और रोजमर्रा के खर्च पर पड़ सकता है। 1 सितंबर से एलपीजी की कीमत, गैस कनेक्शन से जुड़ी ई-केवाईसी प्रक्रिया, विमान ईंधन की कीमत तथा कुछ वाहनों की कीमतों में बदलाव देखने को मिल सकता है। इन बदलावों का असर अलग-अलग वर्गों के परिवारों और उपभोक्ताओं पर पड़ेगा।

सबसे महत्वपूर्ण बदलाव रसोई गैस की कीमतों को लेकर होगा। तेल विपणन कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को घरेलू और वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती हैं। ऐसे में 1 सितंबर को गैस सिलेंडर की नई कीमतें जारी हो सकती हैं। कीमतों में बढ़ोतरी या कमी का सीधा प्रभाव घरेलू बजट पर पड़ेगा। खासकर ऐसे परिवार जिनकी मासिक आय सीमित है, उनके लिए गैस की कीमत में बदलाव महत्वपूर्ण माना जाता है।

इसके साथ ही एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए ई-केवाईसी से जुड़ी प्रक्रिया भी महत्वपूर्ण होगी। गैस कनेक्शन को सक्रिय रखने और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को अपने दस्तावेज और पहचान संबंधी जानकारी अपडेट रखने की आवश्यकता हो सकती है। ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी नहीं होने की स्थिति में उपभोक्ताओं को गैस बुकिंग या संबंधित सेवाओं में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सितंबर में विमान ईंधन यानी एविएशन टर्बाइन फ्यूल की कीमतों में भी बदलाव हो सकता है। विमान ईंधन की कीमतों की समीक्षा प्रत्येक महीने की शुरुआत में की जाती है। इसमें होने वाले बदलाव का प्रभाव विमानन कंपनियों की परिचालन लागत पर पड़ता है। इसका अप्रत्यक्ष असर हवाई किराए पर भी देखने को मिल सकता है। हालांकि किराए में बदलाव कई अन्य कारकों पर भी निर्भर करता है। वाहन क्षेत्र में भी सितंबर से उपभोक्ताओं के लिए कीमतों में बदलाव देखने को मिल सकता है। कुछ वाहन निर्माता कंपनियां नए मॉडल, उत्पादन लागत, कर व्यवस्था और बाजार की परिस्थितियों के आधार पर अपने वाहनों की कीमतों में संशोधन कर सकती हैं। इससे कार खरीदने की योजना बना रहे लोगों के बजट पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा सितंबर की शुरुआत के साथ वित्तीय और उपभोक्ता क्षेत्र से जुड़े कुछ अन्य नियमों तथा शुल्कों में भी बदलाव संभव है। ऐसे में आम उपभोक्ताओं के लिए जरूरी है कि वे महीने की शुरुआत में लागू होने वाले नए नियमों और कीमतों की जानकारी रखें। इन बदलावों का असर रसोई के खर्च से लेकर यात्रा और वाहन खरीदने तक अलग-अलग रूप में दिखाई दे सकता है।

रसोई गैस, ई-केवाईसी, विमान ईंधन और वाहन कीमतों से जुड़े बदलाव आम लोगों के बजट को करेंगे प्रभावित

सिम वाले ईयरफोन की दस्तक, क्या स्मार्टफोन की जरूरत होगी कम?

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: तकनीक की दुनिया में वायरलेस ईयरफोन अब केवल संगीत सुनने तक सीमित नहीं रह गए हैं। नए फीचर्स के साथ ऐसे डिवाइस बाजार में आ रहे हैं, जो स्मार्टफोन की कई जरूरतों को कम करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में प्लॉड वन नाम का नया टू वायरलेस स्टीरियो यानी टीडब्ल्यूएस ईयरफोन पेश किया गया है। इसकी खासियत इसमें दिया गया सिम कार्ड सपोर्ट है।

सिम सपोर्ट की वजह से यह ईयरफोन सामान्य वायरलेस ईयरफोन से अलग हो जाता है। उपयोगकर्ता इसमें सीधे मोबाइल नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकता है। इससे कॉलिंग जैसी सुविधाओं के लिए हर समय स्मार्टफोन पर निर्भर रहने की जरूरत कम हो सकती है। कंपनी ने इसे ऐसे डिवाइस के तौर पर पेश किया है, जिसमें ईयरफोन के साथ कई स्मार्ट क्षमताओं को जोड़ा गया है।

प्लॉड वन में एआई आधारित फीचर्स भी दिए गए हैं। इनका उद्देश्य उपयोगकर्ता के रोजमर्रा के काम को आसान बनाना है। ईयरफोन में बातचीत और अन्य गतिविधियों से जुड़े स्मार्ट फीचर्स उपलब्ध कराए गए हैं। इससे यह केवल ऑडियो डिवाइस न रहकर एक तरह के स्मार्ट सहायक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

प्लॉड वन में सिम कार्ड सपोर्ट के साथ कॉलिंग, एआई और स्मार्ट फीचर्स का दावा

सिम सपोर्ट और एआई फीचर्स का संयोजन इस डिवाइस को बाजार में मौजूद सामान्य टीडब्ल्यूएस ईयरफोन से अलग पहचान देता है। हालांकि स्मार्टफोन को पूरी तरह खत्म कर देने की संभावना फिलहाल व्यावहारिक नहीं मानी जा सकती, क्योंकि फोन में स्क्रीन, कैमरा, ऐप और अन्य कई सुविधाएं होती हैं। इसके बावजूद सिम वाला ईयरफोन पहनने योग्य तकनीक के क्षेत्र में एक नया प्रयोग जरूर है। तकनीकी क्षेत्र में लगातार ऐसे उपकरण विकसित किए जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को कम डिवाइस के साथ अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

सुरक्षित निवेश के साथ नियमित आय, नेशनल सेविंग्स मंथली इनकम अकाउंट की खासियतें

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली:

7.4 प्रतिशत सालाना ब्याज वाली योजना में पांच साल के निवेश से मिल सकती है हर महीने निश्चित आय

नियमित मासिक आय की व्यवस्था करने के लिए पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग्स मंथली इनकम अकाउंट योजना निवेशकों के लिए एक विकल्प बन सकती है। इस योजना में सरकार की ओर से तय ब्याज दर के आधार पर हर महीने निश्चित आय प्राप्त की जा सकती है। वर्तमान में इस योजना में 7.4 प्रतिशत सालाना ब्याज दिया जा रहा है।

पोस्ट ऑफिस की यह छोटी बचत योजना भारत सरकार द्वारा समर्थित है। इसमें निवेशकों को सुरक्षित निवेश के साथ नियमित आमदनी का लाभ मिलता है। यह योजना खासतौर पर ऐसे लोगों के लिए उपयोगी मानी जाती है, जो जोखिम से बचते हुए हर महीने आय चाहते हैं। सेवानिवृत्त लोगों और बुजुर्ग निवेशकों के बीच यह योजना लोकप्रिय है। इस योजना में जमा राशि पर मिलने वाले वार्षिक ब्याज को 12 बराबर हिस्सों में बांटकर हर महीने भुगतान किया जाता है। यदि निवेशक ब्याज की राशि नहीं निकालते हैं तो यह पोस्ट ऑफिस बचत खाते में जमा रह सकती है, लेकिन इस पर अतिरिक्त ब्याज नहीं मिलता। यदि कोई निवेशक इस योजना में 9 लाख रुपये जमा करता है तो 7.4 प्रतिशत ब्याज दर के हिसाब से उसे सालाना करीब 66,600 रुपये ब्याज प्राप्त होगा। वहीं, संयुक्त खाते के तहत 15 लाख रुपये निवेश करने पर सालाना करीब 1,11,000 रुपये ब्याज मिल सकता है। इसे 12 महीनों में बांटने पर हर महीने लगभग 9,250 रुपये की आय प्राप्त हो सकती है।

इस योजना की अवधि पांच साल होती है। अवधि पूरी होने के बाद निवेशक को जमा की गई पूरी राशि वापस मिल जाती है। इसके बाद वह चाहे तो योजना में दोबारा निवेश कर सकता है। नेशनल सेविंग्स मंथली इनकम अकाउंट कोई भी भारतीय नागरिक खोल सकता है। इसके अलावा नाबालिग के नाम पर भी खाता खोला जा सकता है। तीन वयस्क मिलकर संयुक्त खाता भी खोल सकते हैं। 10 साल से अधिक उम्र के नाबालिग के नाम पर अभिभावक की देखरेख में खाता खोला जा सकता है। खाता खुलवाने के लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड जरूरी है। निवेशक को पहले पोस्ट ऑफिस में बचत खाता खोलना होता है। इसके बाद निर्धारित आवेदन पत्र भरकर आवश्यक राशि जमा करने पर मंथली इनकम अकाउंट खोला जा सकता है।

आईटी और मेटल शेयरों में खरीदारी से बाजार में लौटी तेजी, सेंसेक्स-निफ्टी मजबूत

नईदुनिया ब्यूरो, मुंबई: घरेलू शेयर बाजार में शुक्रवार को तेजी देखने को मिली। आईटी और मेटल शेयरों में खरीदारी के चलते सेंसेक्स 331 अंक की बढ़त के साथ 77,265 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 85 अंक चढ़कर 24,176 के स्तर पर बंद हुआ। इससे पहले गुरुवार को बाजार में बड़ी गिरावट दर्ज की गई थी।

शुक्रवार को तापमान सेंसर बनाने वाली कंपनी टेम्पसेंस इंस्ट्रूमेंट्स के शेयर की शेयर बाजार में शानदार शुरुआत हुई। कंपनी का शेयर निर्गम मूल्य से करीब 110 प्रतिशत प्रीमियम पर सूचीबद्ध हुआ। राष्ट्रीय शेयर बाजार पर 300 रुपये के निर्गम मूल्य के मुकाबले शेयर 111.33 प्रतिशत की बढ़त के साथ 634 रुपये पर सूचीबद्ध हुआ। वहीं, बंबई शेयर बाजार पर इसकी लिस्टिंग 110.40 प्रतिशत प्रीमियम के साथ 631.20 रुपये पर हुई। कंपनी का प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम 20 से 24 अगस्त तक खुला था और निवेशकों से इसे अच्छा प्रतिसाद मिला था। इसी बीच ईएसडीएस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन लिमिटेड और प्रायोरिटी ज्वेल्स के प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम शुक्रवार से निवेशकों के लिए खुल गए। ईएसडीएस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन के जरिए 720 करोड़ रुपये और प्रायोरिटी ज्वेल्स के जरिए 91.50 करोड़ रुपये जुटाने की योजना है। दोनों निर्गम 1 सितंबर को बंद होंगे। एशियाई बाजारों में शुक्रवार को मिला-जुला कारोबार रहा। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.79 प्रतिशत गिरा, जबकि जापान का निक्केई 0.41 प्रतिशत और हांगकांग का हैंगसेंग 0.07 प्रतिशत बढ़ा। इससे पहले 27 अगस्त को अमेरिकी बाजारों में भी तेजी रही थी। डाउ जोंस 0.20 प्रतिशत, नैस्डैक 1.57 प्रतिशत और एसएंडपी 500 में 0.72 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई। घरेलू संस्थागत निवेशकों ने पिछले सात दिनों में 14,126 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे। वहीं विदेशी संस्थागत निवेशकों की खरीदारी 2,980 करोड़ रुपये रही। इससे पहले 27 अगस्त को सेंसेक्स 539 अंक गिरकर 76,934 और निफ्टी 117 अंक की गिरावट के साथ 24,091 पर बंद हुआ था।

टेम्पसेंस इंस्ट्रूमेंट्स की शानदार लिस्टिंग, दो नए आईपीओ खुले; एशियाई बाजारों में मिला-जुला कारोबार

स्पेशल खबर पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच कंपनी ने स्थिति स्पष्ट की...

देश में जारी रहेगी ई20 पेट्रोल की बिक्री, ई10 को लेकर प्रस्ताव नहीं

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: देश में ई20 पेट्रोल की जगह ई10 पेट्रोल लाए जाने की चर्चाओं के बीच भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने स्थिति स्पष्ट की है। कंपनी ने कहा है कि ई20 पेट्रोल को हटाकर ई10 पेट्रोल लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर इस तरह की खबरें सामने आ रही थीं, जिसके बाद लोगों के बीच भ्रम की स्थिति बन गई थी।

बीपीसीएल ने साफ किया कि देश में पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण को बढ़ावा देने की नीति के तहत ई20 पेट्रोल का उपयोग जारी रहेगा। ई20 पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल और 80 प्रतिशत पेट्रोल का मिश्रण होता है। सरकार ने पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा बढ़ाने के उद्देश्य से इस दिशा में कदम उठाए हैं।

एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का इस्तेमाल करने का मुख्य उद्देश्य कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करना, प्रदूषण को नियंत्रित करना और किसानों के लिए अतिरिक्त आय के अवसर बढ़ाना है। एथेनॉल का उत्पादन मुख्य रूप से गन्ने, मक्का और अन्य कृषि उत्पादों से किया जाता है।

ई20 पेट्रोल को लेकर वाहन चालकों के बीच कई तरह की चिंताएं भी सामने आई थीं। कुछ लोगों का मानना था कि पुराने वाहनों में इसके इस्तेमाल से प्रदर्शन और इंजन की क्षमता पर असर पड़ सकता है। हालांकि वाहन निर्माता कंपनियों ने नए वाहनों को ई20 ईंधन के अनुकूल बनाने पर काम किया है। बीपीसीएल ने कहा कि ई10 पेट्रोल को दोबारा लागू करने से जुड़ी कोई योजना फिलहाल विचाराधीन नहीं है। कंपनी ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें और अफवाहों से बचें।

एथर लाएगी अपना किफायती इलेक्ट्रिक स्कूटर, मजबूती की हो रही जांच

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी एथर एनर्जी भारतीय बाजार में अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटर कोनार्क लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। कंपनी इस नए मॉडल को किफायती सेगमेंट में पेश कर सकती है। लॉन्च से पहले स्कूटर की मजबूती और टिकाऊपन को परखने के लिए कई कठिन परीक्षण किए जा रहे हैं।

एथर कोनार्क को लेकर कंपनी ने इसके ड्यूरेबिलिटी टेस्ट से जुड़े वीडियो और जानकारी साझा की है। इन परीक्षणों में स्कूटर को अलग-अलग परिस्थितियों में जांचा जा रहा है, ताकि इसकी मजबूती और प्रदर्शन को सुनिश्चित किया जा सके। टेस्ट के दौरान स्कूटर पर भारी दबाव डालकर इसकी बॉडी, सस्पेंशन और अन्य हिस्सों की क्षमता को परखा जा रहा है। कंपनी का उद्देश्य कोनार्क के जरिए इलेक्ट्रिक स्कूटर बाजार में ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों तक पहुंच बनाना है। एथर पहले से ही प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट में अपनी पहचान बना चुकी है। अब नया मॉडल कंपनी को किफायती श्रेणी में प्रतिस्पर्धा करने में मदद कर सकता है। एथर कोनार्क की कीमत को लेकर अभी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन इसे कंपनी के मौजूदा मॉडलों की तुलना में कम कीमत वाले विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक स्कूटर की मांग लगातार बढ़ रही है और कंपनियां नए फीचर्स के साथ किफायती मॉडल पेश करने पर ध्यान दे रही हैं। कोनार्क के लॉन्च के साथ एथर इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की कोशिश करेगी। कंपनी की ओर से स्कूटर की लॉन्च तारीख और तकनीकी विशेषताओं की पूरी जानकारी आने वाले समय में जारी की जा सकती है।